

प्रभावी तिथि। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, दुर्भाग्यवश कुछ आरक्षित उम्मीदवारों को पुनर्वर्तित किया जाना है।

(34) इन कारणों से, हम यह मानते हैं कि दोनों रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें कोई लागत के आदेश के बिना खारिज किया जाता है।

आर.एन.आर

*न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति आर. सी. कथुरिया के  
समक्ष*

झारमल,- याचिकाकर्ता

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

*सी.डब्ल्यू.पी. 2000 की संख्या 6335*

8 मार्च, 2001

*हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994- धारा 175 (1) (क्यू)-  
भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 14 & 226-पंच के पद के लिए  
चुनाव-धारा 75 (1) (क्यू) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसके दो से  
अधिक जीवित बच्चे हैं, वह पंच का पद धारण करने के लिए पात्र नहीं  
है-चाहे वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो- फैसला  
किया, नहीं।*

यह माना गया कि 1994 के अधिनियम की धारा 175 (1) (क्यू) के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं (दो से अधिक बच्चे कहने के लिए 1995 में प्रावधान में संशोधन किया गया है) वह ग्राम सरपंच का पद धारण करने के योग्य नहीं है। यह प्रावधान याचिकाकर्ता को बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता है। यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति को सरपंच का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों को संदेश देना है। जो लोग गाँवों में लोगों का नेतृत्व करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विधानमंडल ने प्रावधान किया है कि दो से अधिक जीवित बच्चों वाला व्यक्ति सरपंच का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा। विवादित प्रावधान किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है।

(पैरा 6 & 8)

सतीश चौधरी, अधिवक्ता- याचिकाकर्ता की ओर से

पालिका मोंगा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा- प्रत्यर्थी के लिए।

### निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, जे (मौखिक रूप से)

(1) क्या धारा 175(1)(क्यू) में शामिल विवादित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति के पास दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, वह गाँव के सरपंच बनने के योग्य नहीं होगा, क्या यह धारा अमान्य है? इस चार याचिकाओं के समूह में उत्पन्न एक संक्षेप प्रश्न है। वकील ने 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6335 में बताया गए तथ्यों का उल्लेख किया है। इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता मार्च, 2000 में सरपंच के रूप में चुने गए थे। यह आशंका जताते हुए कि वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 (1) (क्यू) के प्रावधान को देखते हुए पद धारण करने के योग्य नहीं थे, उन्होंने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वह *प्रार्थना करते* हैं कि इस प्रावधान को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाए। जब यह मामला *लंबित* था, याचिकाकर्ता के मामले की प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। 8 जनवरी, 2001 के आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के 9 बच्चे हैं। इसलिए, धारा 175 (एल) (क्यू) के प्रावधान को देखते हुए, उन्हें सरपंच के पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। आदेश याचिकाकर्ता को भेज दिया गया था। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने का विकल्प नहीं चुना है। हालाँकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रावधान असंवैधानिक होने के कारण, विवादित आदेश असमर्थनीय है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से दावे का उत्तरदाताओं द्वारा खंडन किया गया है। एक लिखित बयान दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

(4) पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया है।

(5) जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या धारा 175 (एल) (क्यू), अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है?

प्रावधान निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:-

**175. "अयोग्यता-(1)** व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य होगा या इस तरह बना रहेगा जो -

(1) से (पी) XXXXXXXX

**(क्यू) दो से अधिक जीवित बच्चे हैं:**

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष की समाप्ति दो से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जाएगा।

(6) उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं (इस प्रावधान को 1995 में दो से अधिक बच्चे कहने के लिए संशोधित किया गया है है) गाँव के सरपंच का पद धारण करने के लिए योग्य नहीं है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इस देश के सामने संख्या के संकट को देखते हुए किया गया है। यह उन छोटे कदमों में से एक है जो लोगों को बड़े परिवार रखने से हतोत्साहित करने के लिए विधानमंडल द्वारा उठाए गए हैं।

(7) श्री चौधरी का तर्क है कि याचिकाकर्ता को नियंत्रित करने वाले धार्मिक सिद्धांत उन्हें चार पत्नियां रखने की अनुमति देते हैं। बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार, उल्लंघनकारी कानून धर्म के खिलाफ है और इस प्रकार, अमान्य है।

(8) हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह प्रावधान याचिकाकर्ता को बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता है। यह उनकी धार्मिक

स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति को सरपंच का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों को संदेश देना है। जो लोग गाँवों में लोगों का नेतृत्व करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विधानमंडल ने प्रावधान किया है कि दो से अधिक जीवित बच्चों वाला व्यक्ति सरपंच का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

(9) श्री चौधरी प्रस्तुत करते हैं कि संसद सदस्यों और विधानसभाओं जैसे अन्य निर्वाचित कार्यालयों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस प्रकार, प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

(10) अन्य मामलों में इसी तरह का प्रावधान करने में चूक के परिणामस्वरूप प्रावधान असंवैधानिक नहीं हो सकता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए यह सलाह दी जा सकती है कि वे विभिन्न अन्य कार्यालयों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाएँ। हालाँकि, जब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 175 (एल) (क्यू) असंवैधानिक है।

(11) बढ़ती संख्या एक राष्ट्रीय समस्या है। आजादी के समय लगभग 30 करोड़ से, हम पहले ही एक 'अरब' की बाधा को पार कर चुके हैं। दृष्टि में आशावाद का कोई ठोस कारण नहीं है। देश में गरीबों के लिए प्रजनन ही एकमात्र मनोरंजन प्रतीत होता है। संख्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। चेक एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। विवादित प्रावधान एक छोटा कदम है। उद्देश्य प्रशंसनीय है। उदाहरण अनुकरणीय है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, इन्हें खारिज कर दिया जाता है। प्रावधान और आदेश को कानूनी और वैध माना जाता है। इन परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

**आर.एन.आर**

*न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल के समक्ष*

लखविंदर सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता

*बनाम*

पंजाब राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

*सीडब्ल्यूपी नंबर 734 of 2000*

20 मार्च, 2001

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961-धारा 27-सहायक पंजीयक द्वारा सोसायटी की प्रबंध समिति को हटाने के लिए अध्यक्ष को नोटिस जारी करना-अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया-स्वतंत्र राय के बिना निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध समिति का निलंबन-सहायक पंजीयक द्वारा दुर्भावनापूर्ण आरोपों का कोई जवाब नहीं देना-सहायक पंजीयक की कार्रवाई उचित नहीं है और याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है-विवादित नोटिस को रद्द करते हुए और सोसायटी की प्रबंध समिति को निलंबन के तहत रखने के आदेश को रद्द करते हुए रिट की अनुमति दी गई

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अध्यक्ष श्री अशोक कुमार को कारणदर्शक नोटिस भेजा गया था और इसे प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य को संबोधित नहीं किया गया था, लेकिन समापन पैरा में उन्हें 15 दिनों के भीतर कारणदर्शक नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा सोसायटी की प्रबंध समिति को हटा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर, सहकारी समितियाँ, कक्कड़ ने अध्यक्ष के कारण बताएँ नोटिस के जवाब पर अपनी टिप्पणी भेजी है। सहायक पंजीयक/सहकारी समितियाँ, अजनाला ने पूरी प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया, -

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा